



The Uttar Pradesh Sugarcane Cess (Repeal) Act, 2025

Act No. 3 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/क्ष्म् हि फ्यू फ्वू

क्ष्म्-१] [क्ष्म् १६ १/२

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

यू[क्ष्म् १६] २ तु ऊज् २०२६

ि क्ष्म् १२] १९४७ 'क्ष्म् १ फूर~

उत्तर प्रदेश शासन

क्ष्म् हुक्ष्म् & १

संख्या २५९ / ७९-पि-१-२०२६-१-क-२३-२०२५

लखनऊ, २ जनवरी, २०२६

अधिसूचना

फोफो/क्ष्म्

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, २०२५ जिससे चीनी उद्योग अनुभाग-३ प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक २ जनवरी, २०२६ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३ सन् २०२६ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, २०२५

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३ सन् २०२६)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिह्नतरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

१-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, २०२५ कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
22 सन् 1956 का
निरसन

2— उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

mnas ; vks dkj.k

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1956) को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में, दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 को दिए गए अपने विनिश्चय में राज्य की विधायी हैसियत से परे और अधिकारातीत घोषित किया गया है।

इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 के विनिश्चय के पश्चात, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 अब अस्तित्व में नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम का निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 259 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-23-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna Upkar (Nirsan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 2026. The Cheeni Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE CESS (REPEAL) ACT, 2025

(U.P. Act no. 3 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane Cess (Repeal) Act, 2025.

2. The Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Act
no. 22 of 1956

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 U.P. Act no. 22 of 1956 has been declared ultra vires and beyond the legislative capacity of the State by the Honorable Supreme Court, New Delhi in its decision given on December 13, 1960 in Diamond Sugar Mills Limited and Others *vs.* State of Uttar Pradesh and Others.

Thus, after the decision of the Honorable Supreme Court dated December 13, 1960, the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 is no longer in existence.

.tcA diaserofa eht laeper ot dediced neeb sah ti ,evoba eht fo weiv nI

.ylgnidrocca decudortni si 2025 ,lliB (laepeR) sseC enacraguS hsedarP rattU ehT

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०य०पी०-ए०पी० 320 राजपत्र-2026-(968)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।
पी०एस०य०पी०-ए०पी० 144 सा० विधायी-2026-(969)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट